

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1155]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ ज्येष्ठ 13, 1937

No. 1155] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015 / JYAISTHA 13, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शुद्धि—पत्र

नई दिल्ली, 26 मई, 2015

का.आ. 1455(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2, खण्ड (क) के अनुसरण में, दिनांक 21 जनवरी, 2014 को असाधारण राजपत्र संख्या 145 में प्रकाशित, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 20 जनवरी, 2014 की अधिसूचना का0आ0 150(अ) के द्वारा, अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई सारिणी के स्तम्भ (1) में वर्णित, श्री रमेश मिश्र, रा. प्र. से. (पी—98), संयुक्त कलेक्टर, रीवा, को, सारिणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित क्षेत्रों के बाबत मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित विभिन्न उपभोक्ताओं तक वितरण के लिए, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (आर०जी०पी०एल०), (जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय मेकर चैम्बर्स—IV (तीसरा तल), 222, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई—400021 (महाराष्ट्र) [पत्राचार पताः प्रथम तल, एम०ए०बी०, रिलायंस कार्पोरेट आई०टी० पार्क, ढाणे—बेलापुर रोड, घनसोली, नवी मुम्बई—400701(महाराष्ट्र)] में है, द्वारा उनकी प्रस्तावित शहडोल (मध्य प्रदेश) —जयसिंग नगर—बेउहारी—गुरह—फूलपुर (उत्तर प्रदेश) गैस पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उक्त अधिनयम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए, मध्य प्रदेश शासन के अधीन उनके वर्तमान कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है:

और, आर0जी0पी0एल0 की उक्त पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए अब, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अस्थाई रूप से सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु, मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत अपने नियमित कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त, अपर कलेक्टर, रीवा के पदधारी को पदेन रूप में नामित किया है:

अतः उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार उक्त अधिसूचना का0आ0 150(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2014 के अन्तर्गत दी गई सारिणी को निम्नांकित रूप में संशोधित किए जाने का निर्देश देती है :--

सारिणी

अधिकारिता का क्षेत्र
(2)

अपर कलेक्टर, रीवा और पदेन सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट द्वारा प्रमुख सचिव, (सामान्य प्रशासन), मध्य प्रदेश शासन, भोपाल (म०प्र०)

मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिले

[फा0 सं0 एल0 -14014/28/2013 - जी0 पी0 - II] श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

2433 GI/2015 (1)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th May, 2015

S.O. 1455(E).—Whereas in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Notification S.O. 150(E) dated the 20th January, 2014, published in Gazette No. 145 dated the 21st January, 2014, authorized Shri Ramesh Mishra, S.A.S. (P-98), Joint Collector, Rewa, as mentioned in column (1) of the Table given thereunder to perform the functions of the Competent Authority under the said Act for laying of pipeline by M/s Reliance Gas Pipelines Limited (RGPL), having its Registered Office at 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222 Nariman Point, Mumbai – 400021 (Maharashtra) [Address for communication: 1st Floor, MAB, Reliance Corporate IT Park, Thane – Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai – 400701 (Maharashtra)] for transportation of natural gas through its proposed Shahdol (Madhya Pradesh) – Jaising Nagar – Beohari – Gurh – Phulpur (Uttar Pradesh) pipeline for distribution to various consumers in respect of the areas mentioned in Column (2) of the said table, in addition to his existing duties and responsibilities under State Government of Madhya Pradesh;

And whereas, the State Government of Madhya Pradesh has now nominated the incumbent of Additional Collector, Rewa, on temporary basis to perform the functions of the Competent Authority under the said Act for the said gas pipeline project of RGPL in all the Districts of Madhya Pradesh State, in ex-Officio capacity, in addition to his duties and responsibilities under the State Government of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of clause (a) of Section 2 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Table given below said notification S.O. 150(E) dated the 20th January, 2014 may be amended in the manner specified hereunder:-

TABLE

Areas of jurisdiction
(2)
All Districts of Madhya Pradesh State

[F. No. L-14014/ 28 /2013-GP - II] S.P. AGARWAL, Under Secy.